(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू) : (क) से (घ) डीजल आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की लागत कोयला, जल तथा गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की तुलना में अधिक होती है। अतः डीजल पर आधारित स्कीमों पर विचार मामले दर-मामले की वरीयता के आधार पर किया जाता है तथा ऐसे स्थानों के मामलों में ही अनुमोदन दिया जाता है जहां पर बिजली की बहुत अधिक कमी होने की प्रत्याशा हो तथा सस्ती बिजली उपलब्ध होने से कम अवसर हों। जिन डीजल आधारित विद्युत संयंत्रों को हाल ही में स्वीकृत किया गया तथा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

स्कीम का नाम/स्थान	राज्य
(क) स्वीकृत	
1. येलाहांका में डीजी संयंत्र— 120 मे0वा0	कर्नाटक
2. कोलार, बीदर जामखंडी तथा इंदी-77.76 मे०वा० (चार स्थानों में प्रत्येक 19.44 मे०वा०) डीजी संयंत्र	कर्नाटक
(ख) के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत	
3. कसारगोडा में डीजी संयंत्र- केरल 60 मे०वा०	
4. ब्रह्मपुरम में डीजी संयंत्र— केरल 100 मे०वा०	

Clearance of power projects launche by Pvt. Sectors Multinationals NRI sponsored companies

225. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SMT. VEENA VERMA:
SHRI RAJNI RANJAN SAH

Will the Minister of POWER pleased to state:

(a) whether any private sector pov projects, including those launched multinational companies and NRI sp sors have been cleared during the p three months since April, 1993; and

(b) if so, the details thereof, indica the additional generating capacity, lil to arise thereby, alongwith the result per capita availablity in the diffe States andn territories as against the India figure?

THE MINISTER OF STATE IN T MINISTRY OF POWER (SHRI P. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) following private sector power pro have been cleared from foreign in ment and since April, 1993:

S. No.	Name of Project	Capacity (MW)	Provisional Est. Cost. (Rs. Crores)	Name of Company
1	Jegurupade GBPP Andhra Pradesh	172	675	GVK Industries Ltd.
2	Kakinada GBPP Andhra Pradesh	200	655	Spectrum Power Mene Ltd.
3	Mangalore TPS Karnataka	1000	2000	Cogentrix Inc., USA
4	Ib Valley TPS Orissa	420	1000	AES Corpn., USA

These projects will be commissioned after some years. Therefore, it is not possible to indicate the resultant per capita availability at this stage as this will depend on the population growth and the projects coming on stream.

Setting up of self employed production units of readymade garments

226. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for setting up of self employed production units of readymade garments in Gandhidham and Gandhinagar District of Gujarat;

(b) whether Reserve Bank of India has also been directed for taking initiatives for providing loans for these units; and

(c) if so, what are the details thereof and the progress made so far in this direction?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Government of India in the Ministry of Textiles have not formulated any scheme for setting up of self employed production units of readymade garments in Gandhidham and Gandhinagar Districts of Gujarat. This Ministry has also no information about any other agency having formulated any such scheme.

(b) and (c) Do not arise.

वस्त्रों के निर्यात के लिये कोटा प्राप्त करने में धोखाधड़ी

227. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेकों संसद सदस्यों ने कुछ फर्मों द्वारा वस्त्रों के निर्यात के लिये कोटा हासिल करने में की जा रही धोखाधड़ी के संबंध में सरकार से शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी)। (क) से (ग) श्री अर्जुन सिंह यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) ने वस्त्र मंत्रालय को लिखित रूप से शिकायत की है कि एक परिधान निर्यातक, मैसर्स मधु गार्मेंटस, नई दिल्ली परिधान के निर्यात कोटाओं को प्राप्त करने के लिये कपटपूर्ण तरीके अपना रहा है। वर्ष 1992 और 93 के दौरान इस विषय पर किसी अन्य संसद सदस्य से कोई अन्य शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

हथकरघा उद्योग के लिये योजना

228. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु 1,162 करोड़ रुपये व्यय वाली योजना को क्रियान्वित किये जाने की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो यह घोषणा कब की गयी थी और क्या यह योजना लागू हो चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो देश के किन-किन स्थानों पर इन योजनाओं के अनुरूप कार्य चल रहे हैं ; और